MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The Motion was adopted.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Articles 94 and 179)

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The Motion was adopted.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR : I introduce the Bill.

17.58 hrs.

OILFIELDS (REGULATION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER : We now take up Legislative Business. Shri P. Shiv Shankar.

THE MINISTER OF ENERGY (SHRI P. SHIV SHANKAR) : Sir, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, be taken into consideration."

Royalty is payable on the crude oil produced and the rate of royalty on the crude oil produced in the country is fixed under the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948. Under this Act, the Central Government shall not—

(a) fix the rate of royalty in respect of any mineral oil so as to exceed 20% of the sale price of the mineral oil at the oil field, or the oil well-head as the case may be,

Or

(b) enhance the rate of royalty in respect of any mineral oil more than once during any period of 4 years.

The last revision in the rate of royalty was effected from 1st April, 1981 when the rate of royalty on the crude was enhanced from Rs. 42 per metric tonne to Rs. 61 per metric tonne. The rate as per the present provisions of the Act cannot be revised before 1st April, 1985.

The Governments of Assam and Gujarat have been representing for the revision in the rate of royalty. As the power of the Central Government to enhance the rate of royalty in respect of any mineral oil is subject to the condition that it cannot be revised more than once during any period of 4 years, it is proposed to modify the relevant provisions of the Act so as to facilitate the Central Government to enhance by revision the rate of royalty *after an* interval of three years.

It is also proposed to avail of the opportunity to amend Section 10 of the Act relating to the laying of rules in accordance with the recommendations of the Committee on Subordinate Legislation.

The Oil Fields (Regulation and Development) Amendment Bill, 1983, seeks to achieve the above objectives.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II Section 2 dated 22.12.1983.

"That the Bill further to amend the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, be taken into consideration."

Now Shri M.M. Lawrence.

18.00 hrs.

SHRI M.M. LAWRENCE (Idukki) : I oppose the amendment, because the Government wants to acquire sweeping powers under this amendment. In general, Government have rule-making powers, but in the case of oilfields, there is a special situation. The workers engaged in extraction of mineral oils are always treated separately, because of the rigours of their task. Hence, there must be circumspection while framing rules. I cite one instance which will show the necessity of such circumspection. The Government nationalized the Assam Oil Company operating at Digboi. It separated the refinery and marketing portions, and handed them over to Indian Oil Corporation. The drilling part has been handed over to the Oil India Ltd., a company which is based in Duliajan. But both these companies function from the same land leased to the Assam Oil Company. Therefore, both these companies come under the Mines Act, while the Factories Act also applies in respect of Indian Oil Corporation.

The Assam Oil Company was in the habit of engaging a large number of contract workers for the purpose of running its day-to-day business in perennial nature of jobs. The mine workers union is the only registered union of contract labourers in both these concerns. According to the earlier practice, contractors used to serve both in drilling as well as in refinery and marketing sections.

SHRI P. SHIV SHANKAR : This does not come under the mines.

SHRI M.M. LAWRENCE : Let me complete my speech. I want to highlights some points.

SHRI P. SHIV SHANKAR : You are welcome.

SHRI M.M. LAWRENCE : The same practice is being continued every day. But the Indian Oil Corporations Management is refusing to negotiate with this Mineral Workers Unions. Similarly, Oil India Ltd. is also not settling their demands so far as the permanent employees are concerned ; they are being deprived of the wages very recently settled in the Indian Oil Corporation. We have no picture as to what emoluments the Oil India Ltd. is paying to its workers and whether it is at par with the O.N.G.C. workers who are similarly engaged in extraction of oil. The question of this contract labour was taken up with the Joint Chief Labour Commissioner (Central) but this could not be settled because of the recalcitrant attitude of the Indian Oil Corporation and its workers have to resort to strike.

I, therefore, take this opportunity to urge the government to settle the demands of the contract labour as well as the erstwhile employees of Assam Oil Company so that no discriminatory treatment is meted out to them.

The service conditions of the workers of erstwhile Assam Oil Company should also be brought at par with the workers of Indian Oil Corporation so that the principle of 'equal pay for equal work' can be upheld. The contract labourers who are engaged in perennial or similar nature of job under the principal employer should also be given the benefits as provided for under Section 25(2)(V)(a) of Contract Labours (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971. With these words, I conclude my speech.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल में रायल्टी की अवधि चार की जगह तीन बरस करने के लिए कहा है, यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि रायल्टी का निर्णय आप किस आधार पर करते हैं। आपको याद होगा कि नागालैण्ड में खोज करने की बात कही गई थी। वहां राज्य सरकार ने स्वामित्व का प्रश्न उठाया था। वह भी रायल्टी से जुड़ा हुआ है। जब आप तीन वर्ष की बात करते हैं तो उस तरह रायल्टी बढ़ जाएगी और कहीं कम भी हो सकती है, ऐसा आपने कहा है। मेरा सुझाव है कि इस रायल्टी का जो निर्णय किया जाता है,

इसकी पद्धति में तबदीली होनी चाहिए जिससे राज्यों को भी जायज हिस्सा मिल सके। छठी पंचवर्षीय योजना का टारगेट था 6541.72 करोड़, वह सरपास होकर 6770 करोड़ हो गया। आपने जो लक्ष्य तय किया है उसकी पूर्ति में नये बेसिन में खोज हुई है। आफशोर के कुछ इलाके हैं जहां पर पैट्रोल की खोज हुई है। नार्थ ईस्ट में, लक्ष द्वीप में, अंडमान आदि में खनिज तेल की खोज के सक्रिय प्रयास किए जाने चाहिए। एक करोड़ टन हम आज बाहर से मंगाते हैं। अगर हमने यहीं अपने देश में सक्रिय प्रयास किए तो उससे स्थिति सुधरेगी। रायल्टी तो आप बढ़ाएं लेकिन साथ-साथ देखें कि प्रोडक्शन कैसे हमारे देश में बढ़ सकती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ती है और पैट्रोल, खनिज तेल आदि अधिक मात्रा में हमारे देश मे उपलब्ध होगा और हमें विदेशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा तब निश्चित रूप से उद्योगों और कृषि को भी इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, देश समृद्ध होगा, सम्पन्न होगा।

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : बहुत विलम्ब से यह बिल यहां लाया गया है। और यह अधूरा बिल है। चार साल के बाद रायल्टी जो बढ़ाई जाती थी या उस पर विचार किया जाता था, अब तीन साल के बाद किया जाएगा, तब उसमें फेरबदल किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि 1976 के बाद 1980 में इसकी अवधि पूरी होती थी तो 1980 में रायल्टी की दर बढ़ाई जानी चाहिए थी जब चार साल पूरे होते थे लेकिन इस दर को अप्रैल 1981 में जाकर बढ़ाया गया। तीन चार मास बाद यह दर बढ़ाई गई। बीस परसेंट के हिसाब से आपको रायल्टी राज्यों को देनी पड़ती है अगर आपने समय पर इसको बढ़ाया होता तो सितम्बर 1981 में क्रूड का भाव 305 के बजाय 1982 के हिसाब से आपको देना होता। इससे राज्यों को ज्यादा मिलता। दुनिया के देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि खनिज सम्पत्ति राज्य सरकारों की सम्पत्ति है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी 1962 में इस बात को स्वीकार किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि रायल्टी की बात जब आएगी तब राज्यों से सम्पर्क किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। अवधि समाप्त होने पर भी इसकी दर को रिवाइज नहीं किया जाता है। भाव ठहराने की पद्धति आपकी खुद की पद्धति है। इस सम्बन्ध में आपने कोई नियम नहीं बनाए हैं। 1962 के बाद 1966 में चार साल के बाद आपको इसको बढ़ाना था लेकिन आपने 1968 में जाकर इसको बढ़ाया, यानी दो साल की आपने इसमें देरी की। इसके बाद 1972 में जो एवार्ड दिया गया उसमें सात साल की अवधि रखी गई थी। उसके बाद जब बहुत हल्ला हुआ तो चार साल के बाद 1976 में जाकर आपने इसको बढ़ाया। यह जो देरी की जाती है यह ठीक नहीं है। सदन के अन्दर और बाहर सभी सदस्यों ने, राज्य सरकारों ने, प्रजातंत्रीय संगठनों ने बार-बार सरकार का इस ओर ध्यान खींचा है और हर बार हमको आश्वासन यह दिया गया है कि यह मामला विचाराधीन है। इन आश्वासनों के बावजूद भी आज इस सत्र के आखिरी दिन छः बजे आप इसको यहां ला रहे हैं। फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं। आपने तीन साल के बाद इसमें फेरबदल करने की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह हर साल क्यों नहीं होना चाहिये। हर चीज के जब भाव हर साल बढ़ाए जाते हैं और दूसरी चीजों के भाव दिन पर दिन बढ़ते हैं जैसे रेलवे फ्रेट, पोस्टेज दिन-पर-दिन बढ़ते हैं तो इसकी दर हर साल क्यों नहीं बढ़नी चाहिये, क्यों यह रिवाइज नहीं होनी चाहिये। काटन के लिए आप हर साल रिवाइज्ड स्प्रोर्ट प्राइस की घोषणा करते हैं। रायल्टी के बारे में तीन साल की अवधि आप क्यों रख रहे हैं। राज्य अलग नहीं है। वे भी भारत का हिस्सा हैं। हमारी धरती के अंग हैं। आपको ज्यादा लाभ होता है तो आप उनको क्यों ज्यादा नहीं देना चाहते हैं। तीन साल के बाद क्यों देना चाहते हैं, हर साल इसमें फेरबदल क्यों नहीं करना चाहते हैं।

रायल्टी तय करने का जो तरीका है अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकार से इसको तय किया जाता है। इसको भी नियमित किया जाना चाहिये। क्रूड से पेट्रोल, कैरोसीन, नेफ्ता आदि सब निकालने के बाद जो कचरा बचता है जिसको

आर० एफ० ओ० कहते हैं, इसका भाव दो हजार प्रति टन पर राज्यों के बिजली बोर्डों और दूसरे उपभोगों को दिया जाता है। जबकि रायल्टी के संदर्भ में इसका भाव 305 रुपये तय किया गया था, बाद में सितम्बर में इसको बढ़ाकर 1182 किया गय । लेने का एक तरीका और देने का दूसरा तरीका, यह ठीक नहीं है। जैन मन्दिरों में देव को घी चढ़ाने के लिए बोली बोली जाती है।

जैन मन्दिरों में लोग 2 टन, 5 टन, 10 टन घी बोलते हैं, सुनकर आश्चर्य होता है। बाजार भाव अगर घी का 100 रु० है तो बोली में 2, ढाई रु० टन का घी माना जाता है। पैट्रोल, तेल, नैप्था निकालकर जो कचड़ा बचता है उसका 2,000 रु० लिया जाता है। गैस जो निकलती है 1965 में हमारे जाने-माने अर्थशास्त्री श्री वी० के० आर० वी० राव ने हिसाब लगाकर बताया था कि 76 रु० प्रति टन इसका भाव होना चाहिये। लेकिन आज गैस जो तेल के साथ मिलती है उसका भाव 2,500 रु० मांगा जा रहा है। तो बेचने का भाव अलग और रायल्टी का भाव अलग। ऐसा क्यों? मैं मांग करता हूं कि बिल में भी सुधार किया जाय और अन्तर्राष्ट्रीय भाव दिया जाय। देने और लेने के बारे में जो अलग-अलग तरीके काम में लाये जाते हैं इसको नियमित किया जाय और अवधि निश्चित की जाय कि रायल्टी की दर भी अन्तर्राष्ट्रीय भाव को देखते हुए तय की जाया करेगी।

कुंए में क्रूड निकालने की अवधि निश्चित होती है। 15-20 साल में कुंए में से क्रूड खत्म हो जाता है। अब तक 50 प्रतिशत तेल तो हमारे कुओं में से निकल चुका है। इसलिये अब तक निकाले गये क्रूड का भी पैसा रायल्टी का न देकर राज्यों के प्रति अन्याय किया जा रहा है। इसमें सुधार किया जाय और रिट्रास्पैक्टिव डेट से दिया जाय। 4 प्रतिशत जो सेल्स टैक्स मिलता था वह भी हमसे खींच लिया गया, जो सरासर गलत है। राज्यों के आज के साधन वैसे भी कम हैं, और जो हैं भी उनको कम किया जा रहा है। इस अन्याय को समाप्त किया जाय और हमारी रायल्टी की दर में सुधार किया जाय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव के साथ जोड़ा जाय। सितम्बर, 1981 में रेट बढ़ाया गया, वह अप्रैल 1981 से दिया जाय।

ओ० एन० जी० सी० को 1980-81 के मुकाबले में 1981-82 में 8 गुना मुनाफा हुआ है। उस मुनाफे का हिस्सा उन राज्यों को भी मिलना चाहिये जिससे कि आपको तेल मिलता है। उन राज्यों की आर्थिक स्थिति तब ठीक होगी मैं आशा करता हूं कि रायल्टी की दरों में सुधार किया जायगा और राज्यों के प्रति न्याय किया जायगा।

जो मैंने सुझाव दिए हैं इनको एक नए संशोधन विधेयक के रूप में अगले सत्र में आप लाएं, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, रायल्टी के बारे में 4 साल के समय को घटा कर जो 3 साल रखा गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह अवश्य चाहता हूं कि रायल्टी का जो शेयर है स्टेटस को ही मिलना चाहिये, और 3 साल जो रखे हैं तो इस पिरियड के अन्दर ही रायल्टी तय करके जो भी शेयर स्टेटस का बनता है वह मिल जाना चाहिये।

जैसलमेर के अन्दर तेल की खुदाई के लिये···

श्री पी० शिव शंकर : अभी तो आपके पास तेल निकला नहीं है और रायल्टी की बात कर रहे हैं?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : खुदाई का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। गोटारू के अन्दर तेल का जो कुआं खोदा गया उसमें एक साल लगा। यह रफ्तार बहुत धीमी है। जब पाकिस्तान के सुई और मारी स्थानों में गैस और पैट्रोल बड़ी तादाद में निकल रहा है तो इस बात की आवश्यकता है कि मशीनें 2, 3, 4 बढ़ाई जाएं और कार्य तीव्र गति से किया जाये। जहां रोड्ज नहीं हैं, वहां हैलीकाप्टर द्वारा मशीनें भेजकर कार्य किया जाना चाहिए ताकि रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास हो सके।

जब पाकिस्तान में इस तरह के डैजर्ट की खोज करके तेल, गैस और पैट्रोल निकल रहा है तो हमारे भी इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिये पूरी ताकत और शक्ति लगाकर तेल निकालने की व्यवस्था की जाये। जब दूसरे कंट्रीज में डैजर्टस में इस प्रकार की सफलता हुई है तो यहां भी सफलता प्राप्त करने की बहुत संभावना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI P. SHIV SHANKAR : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am at a loss as to what exactly should I reply to the debate on this Bill but I thank the hon. Members who have participated in this debate. The amendment is a very simple amendment sought to be brought in 1948 Act reducing the period from four years to three years so that the royalty that is claimed by the States should be settled a little earlier. So it is for that purpose. So far as the other amendment in Section 10 is concerned, that is having regard to the Subordinate Legislation Committee recommendation that all the rules, etc. must be placed on the Table of the House. So, I thank the hon. Members. I have nothing more to say.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> That the Bill further to amend the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 be taken into consideration.

The Motion was adopted.

The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause—2 Amendment of Section 6A

SHRI MOTIBHAI R. CHAUDHARY : I beg to move :

Page 1,—

for Clause 2 *substitute*

'2. In section 6A of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (hereinafter referred to as the Principal Act), in clause (b) of the proviso to sub-section (4), for the words "during any period of four years" the words "a year," shall be substituted.' (1)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put amendment No. 1 to clause 2 to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That Clause 2 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are no amendments to Clause 3. The question is :

> "That Clause 3 stand part of the Bill."

The Motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now the question is :

> "That Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The Motion was adopted.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister may now move that the Bill be passed.

SHRI P. SHIV SHANKAR : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the Bill be passed."

The Motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we go to the next item.

We will now take up Discussion under Rule 193. Of course, Dr. Subramaniam Swamy will take more time. Other hon. Members will not take more than ten minutes. We must finish this discussion, including the reply of the Minister, today. All those members present now shall continue to remain here.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul) : It is confinement.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Dinner has been arranged.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Do not announce it ; go straight to the dining room.

18.26 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA *Contd.*

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha :—

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 21st December, 1983 agreed without any amendment to the Banking Laws (Amendment) Bill, 1983, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th December, 1983."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1983 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 21st December, 1983."

ESSENTIAL COMMODITIES AMENDMENT BILL

As passed by Rajya Sabha

SECRETARY-GENERAL : Sir, I lay on the Table of the House the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1983, as passed by Rajya Sabha.

18.27 hrs.

DISCUSSION ON THE STATEMENT RE : IMPORT OF ANIMAL TALLOW

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East) : Sir, I rise to initiate the discussion on the statement made by Shri Viswanath Pratap Singh, Minister of Commerce, on the 15th November. He is not here.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P.A. SANGMA) : I am here.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Who is going to answer the points raised by us in this debate ?

SHRI P.A. SANGMA : The Minister will reply.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : Fine. I must also take objection...

MR. DEPUTY-SPEAKER : He can hear your voice from his room.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : The room is no substitute for the Chamber.